(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच मौद्रिक नीति, ब्याज दर और फाइनेंशियल सेक्टर लेजिसलेटिव रिफार्म कमीशन की रिपोर्ट को लेकर मतभेद है;

(ख) क्या सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारों में कटौती करने की योजना बना रही है?

(ग) आर्थिक सुधार को लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार की नीतियों में क्या सामंजस्य की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इससे विकास दर कितनी प्रभावित हो रही है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

(क) मौद्रिक नीति तैयार करना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सौंपा गया विशेष अधिदेश है। वित्‍त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक एक नए मौद्रिक ढांचे को तैयार करने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। वित्‍तीय क्षेत्र के विधायी सुधार आयोग की रिपोर्ट की वित्‍त मंत्रालय में आरबीआई सहित विभिन्‍न मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नहीं।

(घ) उपर्युक्‍त (ख) और (ग) के उत्‍तर को देखते हुए प्रश्‍न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*